भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 191
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

एनईपी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल

†191. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल और चुनौतियां हैं जिनमें योजना शुरू करने में विलंब, अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त निधि आवंटन और राज्यों में कार्यान्वयन में असमानताएं शामिल हैं; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अंतरालों को दूर करने, पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने तथा देश में एनईपी के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ख): दिनांक 29.07.2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं, जिसमें इसका विनियमन और प्रशासन भी शामिल है, के संशोधन और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है ताकि एक ऐसी नई प्रणाली का निर्माण किया जा सके जो सतत विकास लक्ष्य-4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप हो और साथ ही भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर आधारित हो।

एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ नियम और कार्यप्रणाली भी दी गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि वर्ष 2030-40 के दशक में पूरी नीति परिचालन मोड में होगी, जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित

मंत्रालयों, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल की है।

एनईपी के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024, 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। दिनांक 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य एनईपी 2020 को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और तरीकों का प्रसार करना है। हाल ही में दिनांक 10 और 11 जुलाई 2025 को गुजरात के केवडिया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें शैक्षिक परिवर्तन के चालकों के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका और वर्ष 2047 के विकासशील भारत में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया; एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की दिशा तय की गई; एनईपी 2020 के प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के तहत बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 30 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक आयोजित की गई, जिसमें एनईपी कार्यान्वयन के लिए यूजीसी विनियम, बहु-विषयक शिक्षा के लिए क्लस्टरिंग और सहयोग, कौशल और उद्योग संपर्क के एकीकरण के माध्यम से समग्र शिक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई।

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के बारे में लोगों तक पहुंच और जागरूकता फैलाने के लिए 84 केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएफआई) और 404 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें प्रत्येक सीएफआई को नजदीक के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 5-7 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का बजट आवंटन निम्नलिखित है:-

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
बजट आवंटन (करोड़ रु. में)	93,224.31	1,04,277.72	1,12,899.47	1,21,117.77	1,28,650.05

****